

जबलपुर : सड़क हादसे में महाकुम्भ से लौट रहे 6 तीर्थ यात्री मरे

जबलपुर, 24 फरवरी। जिले के सिहोरा तहसील के पहरेवा में भीषण सड़क हादसे में छः लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की सुबह ये भीषण सड़क हादसा, खितौला थाने के पहरेवा गांव के नजदीक हुआ। यात्री बस और एक एसयूवी कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में एसयूवी कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार छः लोगों ने मोके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर रेफर



इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी व छः विधायकों के निलम्बन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बायकॉट कर दिया। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेसियों ने सदन से बाहर आकर विधानसभा की सीढ़ीयों पर नारेबाजी की।

■ कर्नाटक के तीर्थ यात्रियों की एसयूवी एक बस से टकरा गई जिससे एसयूवी में सवार सभी 6 यात्री मारे गए।

क्रिया गया है।

प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान और दर्शन कर श्रद्धालु गाड़ी से लौट रहे थे कि सोमवार की तड़के 4:30 उनकी गाड़ी भीषण सड़क हादसे की शिकार हो गई। ये सभी श्रद्धालु कर्नाटक के रहने वाले थे और अपने घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही सिहोरा-खितौला की पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है।

मृतकों की पहचान विरुपक्सि गुमती, बस्वराज कुरति, बालाचंद्र और राजू के रूप में हुई है। वहीं, घायलों की पहचान सदाशिव और मुस्ताफ के रूप में हुई है। बता दें कि 11 फरवरी को इसी रूट पर एक ट्रैवलर गाड़ी टुक से टकरा गई, थी जिसमें आंध्र प्रदेश के आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।

गतिरोध नहीं टूटा, कांग्रेस ने बायकॉट किया, मार्शलों के घेरे में विधानसभा चली

स्पीकर और मुख्यमंत्री की पहल असफल रही, डोटासरा द्वारा "अपशब्दों" पर माफी नहीं माँगने से मामला अटका

जयपुर, 24 फरवरी। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल में हंगामे के साथ शुरू हुई। बाद में गतिरोध समाप्त करने पर चर्चा हुई और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाथी तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी पहल की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में अपने कक्ष में बैठकर संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य नेताओं से गतिरोध तोड़ने के लिए कहा।

विधानसभा में चार दिनों से चल रहा कांग्रेस विधायकों का धरना सोमवार को बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन

■ धरने के दौरान डोटासरा द्वारा स्पीकर के लिये प्रयोग किये गये अपशब्दों की रिकॉर्डिंग किसी विधायक ने स्पीकर को सुना दी। इससे बात और ज्यादा बिगड़ गई।

■ विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को रोकने के लिये पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया तथा वॉटर कैनन का प्रयोग किया।

कर रहे कांग्रेस विधायक बायकॉट की घोषणा कर सदन से बाहर निकल आए। कांग्रेस विधायक जब बाहर निकले तो निलंबित विधायक भी बाहर आए। कुछ देर बाद निलंबित विधायक हाकम अली, जाकिर हुसैन गैसावत, संजय

जाटव जब दोबारा विधानसभा के अंदर जाना चाह रहे थे, तो सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उनको अंदर जाने से रोक दिया। इस समय उनकी सुरक्षाकर्मियों से तौखी नॉक-ड्रांक हुई। स्थिति को बिगड़ता देख वरिष्ठ कांग्रेस

विधायक राजेन्द्र पारोकि ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। इससे पहले, बजट पर बहस के दौरान मार्शलों को घेराबंदी में सदन की कार्यवाही चली, इस बीच कांग्रेस विधायक वैल में नारेबाजी करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एक सदस्य पर सदन को हाईजैक करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने बायकॉट की घोषणा की।

सोमवार को अध्यक्ष वासुदेव देवनाथी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित, 6 विधायकों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आप के 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं, पाला बदलने के लिए'

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह बाजवा ने यह दंभ भिना दावा किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 फरवरी। दिमागी खेल की राजनीति के अन्तर्गत, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रतापसिंह बाजवा ने आज दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक, दलबदल की मंशा से, "मेरे संपर्क" में हैं। पंजाब विधानसभा सत्र से पहले, बाजवा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार 1,000 रुपये के मानदेय के मामले में विचल्य कर रही है, जिसका वादा चुनावों से पहले किया गया था।

कांग्रेस विधायक परगत सिंह ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि राज्य सरकार दम्बे सत्र चलाने की इच्छा ही नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी

विजेन्द्र गुप्ता दिल्ली के स्पीकर बने

नयी दिल्ली, 24 फरवरी। विजेन्द्र गुप्ता सोमवार को सर्वसम्मति से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गये। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा

■ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा प्रोटेम स्पीकर अरविंदर लवली ने स्पीकर पद के लिए गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा।

अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विजेन्द्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका कबिनेट मंत्री मनीषिंदर सिंह सिरसा ने समर्थन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ कांग्रेस विधायक परगत सिंह ने भी इस लय में आगे कहा कि आप पार्टी स्वयम् ही, शीघ्र ही मु.मंत्री भगवंत सिंह मान को बदलने वाली है।

■ आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली में पंजाब सरकार के गेस्ट हाउस, कपूरथला हाउस में मु.मंत्री मान व विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसके बारे में चर्चा है कि यह बैठक, पंजाब के मु.मंत्री को बदलने की कवायद का हिस्सा है।

■ पर, यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस राजनीतिक शतरंज का यह मनोवैज्ञानिक खेल, खेल रही है, आप के दिल्ली की हार के बाद निराश व कुठित विधायकों में विभाजन करवाने के लिए।

शीघ्र ही मुख्यमंत्री भगवंत मान को बदल देगी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुये (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुल 400 करोड़ रूपए की पैनल्टी से राहत मिल सकती है, करदाताओं को

- यादवेंद्र शर्मा -

जयपुर, 24 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनील अग्रवाल समेत 9 याचिकाकर्ताओं द्वारा "सेन्ट्रल सर्कल" असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के तहत गलत तरीके से "पैनल्टी" लगाए जाने के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अयनवीश जिन्नाम और न्यायाधीश शुभा मेहता ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, और इनकम टैक्स विभाग द्वारा भविष्य में टैक्सदाता के खिलाफ अवांछित कार्यवाही करने के खिलाफ मौखिक टिप्पणी भी की है। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका परेवी के लिए पेश हुए थे।

दरअसल सुनील अग्रवाल के साथ कई अन्य टैक्सदाता थे, जिनको इनकम टैक्स के

अधिकारियों ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 69-सी व 69-ए के तहत नोटिस भेजा था, जिसके तहत टैक्सदाता के द्वारा किसी भी सम्पत्ति जेवर, गहना, सोना या अन्य मूल्यवान वस्तु की खरीद के सम्बन्ध में उपयुक्त दस्तावेज या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाने या उस वस्तु को खरीदने के लिए आय का खोत नहीं दर्शा पाने पर नोटिस भेजा जाता है।

हैरानी की बात है कि 1 अक्टूबर 2024 को 'एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स' द्वारा इनकम टैक्स की धारा 271-ई के तहत इन सभी टैक्स दाताओं पर पैनल्टी लगाने का

■ अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इनकम टैक्स एक्ट के तहत निर्धारण अधिकारी (असैसिंग ऑफिसर) की रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष या तथ्य पैनल्टी लगाने के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कमिश्नर व अदालतें करदाताओं पर पैनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं कर सकती।

■ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों का हवाला देते हुए यह आदेश दिए।

नोटिस जारी कर किया गया। उल्लेखनीय है कि 271-ई के तहत उन टैक्सदाताओं पर पैनल्टी लगाई जाती है, जिन्होंने 20,000/-

से अधिक की रकम का कर्ज नगद में चुकाया हो चाहे वह लोन उसके नाम पर हो या संस्था के नाम। इनकम टैक्स एक्ट के तहत

हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े कुछ याचिकाकर्ताओं को राहत दी

20,000/- से अधिक का लोन बैंक या अन्य ऑनलाइन बैंकिंग माध्यमों से ही चुकाया जा सकता है, ताकि इसका रिकॉर्ड अधिकारियों को उपलब्ध हो सके।

हैरानी की बात है कि इन सभी टैक्सदाताओं के खिलाफ निर्धारण अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई भी टिप्पणी या निष्कर्ष नहीं लिखा था, जिसके आधार पर इन टैक्सदाताओं के खिलाफ धारा 271-ई के तहत कार्यवाही हो सकती थी।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और 13 हाईकोर्ट और 13 'एपिलेट टिब्यूनल' में दिए गए निर्णयों को आधार बनाते हुए कहा कि

अगर निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य या निष्कर्ष रिकॉर्ड पर नहीं लिखा गया है, जिससे टैक्सदाता पर कोई पैनल्टी लगाई जाए तो इनकम टैक्स कमिश्नर या अन्य अपीलेंट अदालतें टैक्सदाता पर पैनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं कर सकते।

उल्लेखनीय है कि सेन्ट्रल सर्कल के इनकम टैक्स असिस्टेंट व जॉइंट कमिश्नर ने कई और मामलों में कार्यवाही का यही तरीका अपनाया है। इस पर अदालत ने कठोर टिप्पणी की है।

उल्लेखनीय है कि इन मामलों में कुछ मामले अभी हाईकोर्ट नहीं पहुंचे हैं, परन्तु जल्द ही दायर कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सेन्ट्रल सर्कल के अफसरों की ऐसी कार्यवाहियों में करीब 400 करोड़ रु. की कुल पैनल्टी लगाई गई थी।

'करतारपुरा नाले से अतिक्रमण हटाने पर अब तक क्या कार्यवाही हुई'

जयपुर, 24 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने करतारपुरा नाले में हुए अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 26 मार्च तक मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी पेश की जाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) विज्ञान शाह ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर नाले की चौड़ाई के संबंध में जानकारी दी। एएजी ने तीन साल पहले हुई बैठक का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि 13 जनवरी, 2022 को जेडीए अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि करतारपुरा नाले की चौड़ाई तीस मीटर रहेगी और नाले के दोनों ओर दस-दस मीटर की जमीन सुरक्षा कॉरिडोर के लिए

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

आरक्षित रखी जाएगी। इस निर्णय के बाद नाले का पीटी सर्वे किया गया, जिसमें सामने आया कि नाले में करीब पांच सौ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इनमें से 403 अतिक्रमणों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं, 17 अतिक्रमियों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। अन्य अतिक्रमियों को नोटिस जारी करने के साथ ही शेष कार्यवाही की जा रही है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि करतारपुरा नाला बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है। नाले के पक्का नहीं होने और फेंसिंग नहीं लगाने के चलते यहां अतिक्रमण और हादसे हो जाते हैं। इसके अलावा, अभी तक नाले की सीमा भी तय नहीं की है, जिसके कारण नए अतिक्रमण भी नहीं रुक रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फड़नवीस व शिंदे के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं

ऐसा लगने लगा है कि जैसे मु.मंत्री फड़नवीस की पहली प्राथमिकता पूर्व मु.मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्णयों की कमी निकालना व और उनके पुराने आदेशों को पलटना ही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 फरवरी। महाराष्ट्र की देवेन्द्र फड़नवीस सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ एक के बाद एक दूसरा ऑर्डर निकाला है। यह आदेश महाराष्ट्र में मिनिमम सपोर्ट प्राइज की योजनाओं के संचालन के लिए नोडल एजेंसियों के

जो फैसेले लिए हैं, उनसे शिंदे खासतौर पर ज्यादा नाराज है। भाजपा-नीत सरकार ने फरवरी में शिंदे सरकार का 1,400 करोड़ रूपए का टैंडर कैंसिल कर दिया। शिंदे सरकार ने शौचालयों, सड़कों व झुग्गी की सफाई के लिए यह टैंडर बी.एम.सी. को दिया था। शिवसेना नेता इंस बात पर भी नाराज हैं कि फड़नवीस सरकार ने उनके क्षेत्र के जिलों नासिक

■ फड़नवीस के इस एक सूत्री कार्यक्रम के जवाब में शिंदे ने अप्रत्यक्ष धमकी देते हुए कहा, "मुझे हल्का समझने की गलती न करे कोई। 2022 में भी मुझे हल्का समझा गया और मुझे राज्य सरकार को गिराना ही पड़ा और एक "डबल इंजन" की सरकार बनानी पड़ी। मैं एक साधारण कार्यकर्ता जरूर हूँ। पर, बाला साहब ठाकरे का अनुयायी हूँ, यह भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए।"

■ हाल ही में मु.मंत्री फड़नवीस ने, पूर्व मु.मंत्री शिंदे पर जाँच भी शुरू करवा दी, जैसे, 900 करोड़ रूपए की लागत की शिंदे सरकार की हाजसिंग स्कीम पर जाँच बिठा दी है।

■ इसी प्रकार मु.मंत्री फड़नवीस ने शिंदे सरकार द्वारा बीएमसी (बृहत् मुम्बई कॉरपोरेशन) के रख रखाव व साफ-सफाई आदि का, 1,400 करोड़ रूपये की लागत का ठेका भी निरस्त कर दिया है।

चयन में हुई गड़बड़ियों की जाँच के बारे में है। फड़नवीस सरकार ने इससे पहले शिंदे द्वारा घोषित हाजसिंग योजना में हुए 900 करोड़ रूपए के घोटाले की जाँच का आदेश भी दिया है।

फड़नवीस और शिंदे दोनों ही एक दूसरे के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। गत सप्ताहों के घटनाक्रम से संभवतया तनाव और बढ़ सकता है। फड़नवीस ने हालिया सप्ताहों में

व रायगढ़ में उनकी पार्टी के मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन मंत्री घोषित करने की उनकी माँग नहीं मानी। यह भी खबर है कि सरकार ने शिवसेना के कई विधायकों की सुरक्षा घटा दी है।

तनाव के कई अन्य संकेत भी मिल रहे हैं। शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत कोष की तर्ज पर उपमुख्यमंत्री हैल्थ रिलीफ फंड बनाया है। उपमुख्यमंत्री ने एक पैरल समानान्तर वॉर रूम भी बनाया है। गत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टालिन ने मोदी से सीख ली: अभी से 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे

तैयारी के तहत, पूरा प्रचार करने में जुट गये हैं कि केन्द्रीय सरकार नई शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु पर हिन्दी थोपने को तत्पर है

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 फरवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भाषा के मुद्दे पर तो इमोशनल छक्के लगा ही रहे हैं, इसके साथ-साथ अब उन्होंने 2026 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए "गवर्नर्स डिलिवरी" का रास्ता भी अपनाया है। अर्थात् वो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं व नीतियों को क्रियान्वित हो।

पूर्व के विपरीत, सन् 2021 में विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य की सत्ता संभालते ही स्टालिन, भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी की तरह चुनाव अभियान मोड में आ गए थे। अभी तक अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने

■ भाषा के भावात्मक मुद्दे के बाद, स्टालिन अब 2026 के चुनाव की दृष्टि से शिक्षा और हैल्थकेयर स्कीम पर फोकस कर रहे हैं तथा लाइलाज बीमारियों, जैसे डायबिटीज व ब्लडप्रेसर की दवाई को सस्ते न्यूनतम दामों पर उपलब्ध कराने के लिये "मुदालवर मरुन्धगम्" (मु.मंत्री की फार्मसी) की व्यापक योजना बनाई है। इन फार्मसी की दुकानों को चलाने वालों को सरकार की तरफ से "सब्सिडी" भी दी जायेगी। इन क्रॉनिक बीमारियों की दवाई 75 प्रतिशत डिस्काउंट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

■ इन दवा की दुकानों के जरिए स्टालिन दो मैसेज देना चाहते हैं. विशेषकर तमिलनाडु के मध्यम वर्ग को, कि सस्ती दवाइयों मिलना बहुत राहत देगा तथा केन्द्रीय सरकार चाहे जितने भी रोड़े अटकाये, स्टालिन की सरकार अपनी जनता को, राहत पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

"गवर्नर्स डिलिवरी" मॉडल पर खास ध्यान दिया है और साथ ही साथ ग्रोथ व डवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, तथा अक्सर डेटा के माध्यम से उपलब्धि की बात करते हैं। चाहे वो ग्रोथ

हो या सामाजिक संकेतक अथवा अन्य आर्थिक मापदंड, वे अपने भाषणों में इनका उल्लेख करते थकते नहीं हैं। अभी तक वे भाग्यशाली रहे हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है और फिल्म स्टार विजय

की राजनीति में एन्टी उन्हें फायदा अधिक देगी, नुकसान नहीं।

लेकिन वर्तमान में उनका फोकस रेवडियों के वितरण तथा नए और पुराने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों-पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अन्नदाता की सेवा, उन्नति और खुशहाली को एकमात्र

- 'अन्नदाता की उन्नति और खुशहाली राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय'
- 'किसानों के सशक्तीकरण के लिए बजट में की अहम घोषणाएं'

ध्येय मानकर राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के किसान कल्याण और उद्यान के संकल्प को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभांशित किसानों को बधाई देते हुए कहा कि योजना के तहत आज प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि आज का यह समारोह प्रधानमंत्री के किसानों को खुशहाल बनाने के संकल्प और समर्पण की एक मिसाल है। देश को प्रधानमंत्री की गारंटी पर पूरा भरोसा है। शर्मा आज जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह से वीसी के माध्यम से राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस बजट में अन्नदाता को संबल देने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने की घोषणा की है। अब तक मुख्यमंत्री किसान



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में सोमवार को कृषि संबंधी विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लगभग 46 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालिक फसली ऋण उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमारी सरकार द्वारा योजना के तहत लगभग 3100 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए जा चुके हैं।

शर्मा ने कहा कि बजट में किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, ताकि किसानों की समृद्धि की राह खुल सके। बजट में करीब 34 हजार सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई के लिए अनुदान के प्रावधान, आगामी वित्त

वर्ष में 25 हजार फार्म पौड, 10 हजार डिगियों, 50 हजार सौर पंप संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान के प्रावधान किए गए हैं। इन योजनाओं से प्रदेश के 4 लाख किसान लाभांशित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान श्रीअन्न बाजरे के उत्पादन में देशभर में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से इसके उत्पादन में किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मिड-डे-मिल कार्यक्रम तथा मां-बाड़ी केंद्रों में पायलट आभार पर, श्रीअन्न आधरित उत्पाद तथा हर जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अगले वित्त वर्ष में ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट का आयोजन, ढाई लाख

मिलिट्री अस्पताल में मेगा मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन



मिलिट्री अस्पताल जयपुर में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदरसिंह और सप्तशक्ति कमान की क्षेत्रीय आवा अध्यक्ष वरिंदरजीत कौर के द्वारा मेगा मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन किया गया।

जयपुर। मिलिट्री अस्पताल जयपुर में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदरसिंह और सप्तशक्ति कमान की क्षेत्रीय आवा अध्यक्ष वरिंदरजीत कौर के द्वारा मेगा मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल प्रदान करना है जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा के लिये समर्पित कर दिया है।

शिविर के दौरान आर्मी मेडिकल

कोर के एक उच्च नेत्र सर्जन और आरएंडआर अस्पताल दिल्ली के नेत्र विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विशेषज्ञ नेत्र सर्जनों की टीम 24-28 फरवरी तक लाभांशियों को मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी, आंखों की जांच और उपचार करेगी। इस टीम में लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान अग्रवाल, लेफ्टिनेंट कर्नल रवि चौहान और मेजर अमृता जोशी शामिल हैं। चार दिनों की अवधि में टीम 300 से अधिक

मोतियाबिंद सर्जरी तथा दिग्विज्ञों एवं उनके परिवारों के लिये पूरी तरह से आंखों की जांच करेगी और समग्र नेत्र देखभाल के लिये चश्मे और आवश्यक दवाएं वितरित करेगी।

आर्मी कमांडर ने अपने संबोधन में कहा कि शिविर को सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध किया गया है। इसमें प्राथमिक रूप से नेत्र देखभाल और स्वास्थ्य दृष्टि को बढ़ावा देने के लिये विशेष सर्जिकल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कोई यह चाहे कि सदन को हाईजैक कर ले, यह बर्दाशत नहीं होगा : देवनानी

- 'पिछले दिनों मंत्री की एक टिप्पणी को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्य डायस पर चढ़ गए थे। डायस पर चढ़ना ही सदस्य का स्वतः निलंबन होता है। मजबूरी में हमने छह विधायकों का निलंबन किया'

जयपुर (वि.सं.)। विधानसभा में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हर संभव प्रयास किया लेकिन कांग्रेस

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की हठ धर्मिता के कारण यह प्रतिरोध समाप्त नहीं हो सका। इस पर देवनानी ने सदन में अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सदन में गतिरोध तोड़ने के लिए हमने बहुत प्रयास किए, क्योंकि यह सदन प्रदेश के आठ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, "हमने विधानसभा सत्र की शुरुआत में सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा होती है और सदन कैसे सुचारु रूप से चले, इस पर

विमर्श होता है।"

प्रश्नकाल में खड़े होकर बोलना गलत परंपरा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि कुछ लोग प्रश्नकाल की व्यवस्था का पालन नहीं करते और बार-बार खड़े होकर प्रश्नकाल को बाधित करते हैं। राज्यपाल के अधिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब मुख्यमंत्री का संबोधन था, तब भी फोन टैपिंग को लेकर गतिरोध उत्पन्न किया गया।

अवरोध के बीच ही मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ। पिछले दिनों मंत्री की एक टिप्पणी को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्य डायस पर चढ़ गए थे। डायस पर चढ़ना ही सदस्य का स्वतः निलंबन होता है। मजबूरी में हमने छह विधायकों का निलंबन किया। इसके बाद भी गतिरोध समाप्त करने के लिए चर्चा कर हरसंभव प्रयास किए गए।

अध्यक्ष देवनानी ने कहा, "आज

भी विपक्ष के प्रमुख लोगों ने आश्वस्त किया था कि सदन चलाने में सहयोग करेंगे। हमने निलंबन के बावजूद सदन में आने की अनुमति दी, लेकिन जो तय हुआ था उसका उल्टा हुआ। आज भी जब दोबारा डायस पर चढ़ने का प्रयास किया गया, तब जाकर हमें मार्शल बुलाने पड़े। मार्शल और सत्ता पक्ष ने भी संयम से काम लिया। हमने आज भी वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वे हठधर्मिता पर अड़े हैं। यह बर्दाशत नहीं होगा। कोई यह चाहे कि सदन को हाईजैक कर ले, यह बर्दाशत नहीं होगा। डायस पर चढ़ना अनुशासनहीनता है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम होगा।"

अयोध्या में प्रभु श्रीराम के डॉ. पूनिया ने दर्शन किये

अयोध्या। हम करोड़ों सनातनियों के आदर्श, सबके आराध्य प्रभु श्रीराम के अयोध्या में भाजपा हरियाणा प्रभारी, भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने धर्मपत्नी मोहिनी पूनिया के साथ दर्शन कर देशवासियों की खुशहाली की कामना की।

सतीश पूनिया ने कहा कि, सदियों के लम्बे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर में प्रभु श्रीराम को उनके स्थान पर विराजमान देख हृदय अत्यंत भावविभोर है, भगवान श्रीराम के दिव्य दर्शन में लिए अविस्मरणीय क्षण है, यह देश दुनिया में बसे हिंदुओं के लिए गर्व के क्षण है। प्रभु श्रीराम से राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना करता हूँ। सतीश पूनिया ने प्रभु श्रीराम के चरणों में सेदंन कर कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन कर पुरानी स्मृतियां जीवंत हुईं, 500 वर्षों का संघर्ष और लाखों लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन बलिदान के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वह अदभुत है।

गहलोत पहले अपने कार्यकाल में हुई कम खरीद की करे चिंता : दक

जयपुर। प्रदेश के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर जवाब दिया है। दक ने कहा कि गहलोत ने किसानों के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता और मृंगफली किसानों को नुकसान के बारे में जो बयान दिया है वह पूरी तरह झूठा और निराधार है। उन्होंने कहा कि गहलोत को पहले अपनी सरकार के कार्यकाल में हुई कम खरीद की चिन्ता करनी चाहिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश में अब तक लगभग 3.72 लाख मीट्रिक टन मृंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। जो की सरकार को सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह गत पांच वर्षों में सर्वाधिक मृंगफली की खरीद है। उन्होंने बताया कि मृंगफली खरीद के लिए 1.33 लाख से अधिक किसानों से पंजीकरण करवाया था, जिनमें से अब तक 1 लाख से अधिक किसानों से खरीद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 2527 करोड़ रुपये की मृंगफली खरीद की गई है और लगभग 1535 करोड़ रुपये का किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है। दक ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में खरीद के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि

- 'गहलोत सरकार के चार वर्षों से दोगुनी से अधिक मृंगफली की एक वर्ष में की खरीद'

वर्ष 2020-21 में 31,720 किसानों से 389.43 करोड़ राशि की महज 73 हजार मीट्रिक टन मृंगफली खरीदी गई थी। जबकि, वर्ष 2021-22 में 23,562 किसानों से 295 करोड़ राशि की महज 53 हजार मीट्रिक टन मृंगफली खरीदी गई।

इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 में केवल 571 किसानों से 5.92 करोड़ रुपये की 1012 मीट्रिक टन मृंगफली खरीदी की गई थी। वहीं, वर्ष 2023-24 में भी 19,272 किसानों से 296.23 करोड़ रुपये की महज 46 हजार मीट्रिक टन मृंगफली की खरीद हुई थी।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में चार वर्षों में जितनी मृंगफली की खरीद की गई उससे दोगुनी से ज्यादा मृंगफली की खरीद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक वर्ष में ही कर ली गई है।

'निलंबित विधायकों को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए'

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का असभ्य आचरण बेहद शर्मनाक है। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष आक्रामक इशारे दिखाने और जानबूझकर सदन में गतिरोध पैदा करने पर निलंबित विधायकों को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस महज तिल का ताड़ बनाकर बजट सत्र पर बहस से भागने का प्रयास कर रही है। सरकार के मंत्री वार्ता के जरिये गतिरोध खत्म करवाने के लिए प्रयासरत है परन्तु कांग्रेस हठधर्मी रवैया छोड़ने को राजी नहीं है। राठौड़ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के कुछ नेता यह नहीं चाहते हैं कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो। इसलिए ही राज्यपाल अधिभाषण के दौरान भी जानबूझकर गतिरोध पैदा करके उनका भाषण नहीं होने दिया गया था। राठौड़ ने कहा कि आज कांग्रेस का विधानसभा घेराव का प्रदर्शन भी पूरी तरह से फ्लॉप है जिससे यह साफ है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा ही नहीं है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अफसरों को डी.जी.पी. ने सम्मानित किया

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में सोमवार को राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक, डीजीपी डिस्क, अति उत्कृष्ट सेवा पदक व उत्कर्ष सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया।

परेड में चतुर्थ एवं पांचवी बटालियन आरएसी, जयपुर आयुक्तालय की महिला पुलिसकर्मी, आयुक्तालय जयपुर के पुरुष पुलिस कर्मी व यातायातकर्मी, हाड़ी रानी महिला बटालियन, अजमेर, ईआरटी पांचवी बटालियन आरएसी, जयपुर एवं राजस्थान पुलिस अकादमी से एक-एक कुल आठ प्लाटून सम्मिलित हुईं।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी आने वाले समय में और अधिक जोश में ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में प्रदत्त कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करें।

केंद्रीय गृह मंत्री पद से सम्मानित होने वाले पूर्व महानिरीक्षक पुलिस गौरव यादव, पुलिस आयुक्त अमित कुमार, सहायक पुलिस उपायुक्त गुमानाराम, पूर्व पुलिस निरीक्षक अमित सिहाग (मरणोपरान्त), पुलिस निरीक्षक सज्जन कैवर् एवं पूरुम चौधरी, सहायक पुलिस निरीक्षक मदनलाल मीणा, हेड कॉन्स्टेबल पूराराम शामिल हैं। कार्यक्रम



पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक, डीजीपी डिस्क, अति उत्कृष्ट सेवा पदक व उत्कर्ष सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया।

में मरणोपरान्त गृह मंत्री पदक से सम्मानित अमित सिहाग की पत्नी संतोष चौधरी ने सम्मान प्राप्त किया।

डीजीपी डिस्क से सम्मानित होने वालों में महानिरीक्षक (एसीबी) डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा, महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस) संजय अग्रवाल, महानिरीक्षक (जेल) गोविंद गुप्ता, अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग) मालिनी अग्रवाल,

- केंद्रीय गृहमंत्री पदक से सम्मानित हुए 8 पुलिस अधिकारी

शेर एवं कैलाश चंद्र जाट (सेवानिवृत्त), उप महा निरीक्षक हरेंद्र कुमार महावर, राहुल कोटोकी, डॉक्टर राहुल जैन, राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राठौड़, उप महानिरीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ रामेश्वर सिंह, पुलिस अधीक्षक गौरव यादव, अरशद अली, चूनाराम जाट एवं सुधीर चौधरी शामिल हैं।

महानिरीक्षक, एसीबी डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा, महानिरीक्षक एएससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी, महा निरीक्षक पुलिस रवि दत्त गौड़, पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, महानिरीक्षक पुलिस जय नारायण, महानिरीक्षक पुलिस सत्येंद्र सिंह, महानिरीक्षक पुलिस (सेवानिवृत्त) सवाई सिंह गौदारा, उप महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश, उप महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) समीर कुमार सिंह, उपमहानिरीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल शामिल हैं।

सम्मानित होने वाले अधिकारियों में अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस अनिल पालीवाल, पुलिस आयुक्त बीजू जाजं जोषेफ, अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस बिनोता ठाकुर, संजीव कुमार, विशाल बंसल, विजय कुमार सिंह शामिल हैं।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना

जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा दिनांक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) का आयोजन 27 फरवरी एवं 28 फरवरी को तीन पारी में जयपुर शहर के 233 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी जिसमें कुल 2 लाख 70 हजार 18 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर

(पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर परीक्षा के सुचारु एवं सफल संचालन के लिये कलेक्ट्रेट कर कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष का संचालन 25 फरवरी प्रातः 6 बजे से 28 फरवरी को परीक्षा समाप्ति पश्चात परीक्षा सामग्री जिले से रीट कार्यालय अजमेर के

पुंकेश मीणा निवासी हरमांडा जयपुर एवं महेश पुनिया निवासी गांध बीपर फतेहपुर जिला सीकर के पास है। युआएड.सर्व करने पर ऑल नाम की पेनल आईडी खुलती है जिसमें वे अपने स्वयं की कस्टमर आईडी तथा पासवर्ड लगाकर चालू करते हैं।

उनके साथी महेश पुनिया इस पेनल पर कस्टमर आईडी बनाकर ग्राहकों को देता है। महेश ही इन आईडी पर किराये पर लिए बैंक खाता लगाता है। एमडी पेनल पर उनके खाते का क्यू आर कोड लगाते हैं, जिस पर खेलने वाला व्यक्ति रकम लगाते हैं, उक्त रकम किराये के खातों में आ जाती है। जिसे वे अपने इन्टरनेट खातों में ट्रांसफर कर हार-जीत होने के बाद एमडी पेनल पर विड्रॉल करते हैं। यह सब काम ऑनलाइन और प्रतिदिन होता है, जिसका हिसाब ऑनलाइन ही रहता है।

इस सम्पूर्ण काम का रिकार्ड महेश पुनिया के पास है। ऑनलाइन 20-20 तीन पत्ती आईसी, बॉलिवुड कसौती, मिनी सुपर ओवर, गॉल, लकी 15, गोल्डन रौलेट, 32 काइस, वन कार्ड वन डे सहित कुल 70 प्रकार के ऑनलाइन गेम खिलवाते हैं।

एजीटीएफ के उप निरीक्षक सुभाष सिंह तंवर के नेतृत्व में की गई इस संपूर्ण कार्रवाई में एएसआइ शंकर दयाल शर्मा व हैड कॉन्स्टेबल कमल सिंह की विशेष भूमिका तथा हेड कॉन्स्टेबल सुरेश कुमार, नरेंद्र सिंह, कॉन्स्टेबल नरेश कुमार, रतिराम व चालक सुरेश कुमार का सहायनीय योगदान रहा। कार्रवाई में मानसरोवर थाने से उप निरीक्षक अशोक कुमार, हैड कॉन्स्टेबल अशोक कुमार, कॉन्स्टेबल नवीन कुमार, भरत लाल, विष्णु शामिल थे।

